

संपादकौय

पेपर लीक पर अब कड़ी सजा

देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में आज सबसे बड़ी खबर पेपर लीक मामले को लेकर ही चल रही है। जहाँ एक ओर जंत-मंतर पर छात्र पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं तो विपक्षी भी अब इस मामले को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक में हंगामा कर रहे हैं। वहीं सरकार भी एक के बाद एक मॉर्टर कर रही है। आखिर इस मुद्दे को कैसे समाप्त किया जा सके। छात्रों की ज्यादातर मांगों से सरकार सहमत नहीं है। सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर जब कि छात्रों के संगठन सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से कम कोई बात नहीं होगी। नीट भर्ती परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में संगठित आंदोलन के खिलाफ कानून को और अधिक सख्त बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल, 210 करोड़ तक के जुर्माने और मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक संसद में पेश किया जाना प्रस्तावित है। आखिर नया कानून क्यों जरूरी पड़ा? पेपर लीक केवल एक अपराध नहीं, बल्कि लाखों छात्रों की मेहनत, समय और विश्वास पर हमला है। एक परीक्षा के रद्द होने से अर्थर्थियों को महंगी की तैयारी दोबारा करनी पड़ती है। कई उम्मीदवार उम्र सीमा के करीब पहुंच जाते हैं, आर्थिक बोझ बढ़ता है और मानसिक तनाव भी गहरा जाता है। इन्हीं कारणों से सरकार पर लगातार दबाव था कि केवल रिपरायरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए जो पेपर लीक के पूरे नेटवर्क को तोड़ सके। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार— पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा। दोषियों पर 210 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। न्यूनतम सजा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ताकि अपराधियों आसानी से बच न सकें। पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था होगी, जिससे मामलों का जल्द निपटारा हो सके। संगठित गिरोह, संस्थानों और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ या धोखाधड़ी में शामिल पाए जाएंगे। क्या केवल कठोर सजा से समस्या खत्म होगी? कानून का सख्त होना आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। यदि परीक्षा करने वाली संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेगी तो केवल सजा का डर अपराधियों को पूरी तरह नहीं रोक पाएगा। आवश्यक है कि— प्रत्येक तैयार करने से लेकर वितरण तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल सुरक्षा के दायरे में हो। परीक्षा केंद्रों की निगरानी मजबूत की जाए। साइबर सुरक्षा को आधुनिक बनाया जाए। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी समान रूप से कार्रवाई हो। जांच समयबद्ध और निष्पक्ष हो। लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। कई छात्र मानते हैं कि मेहनत से अधिक महत्व भ्रष्ट नेटवर्क का हो गया है। ऐसे माहौल में केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से ही विश्वास बहाल होगा। यदि हर मामले में त्वरित जांच, समय पर आरोप पत्र और शीघ्र सजा सुनिश्चित होती है, तो यह हम कानून वास्तव में निवारक साबित हो सकता है। सरकार के सामने अगली परीक्षा- सरकार ने कड़ा संकेत देने की कोशिश की है कि पेपर लीक अब सामान्य अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या जांच एजेंसियां बड़े गिरोहों तक पहुंच पाती हैं, क्या प्रभावशाली लोगों पर भी समान कार्रवाई होती है और क्या भविष्य में परीक्षाएं बिना विवाद के संपन्न हो पाती हैं। पेपर लीक के खिलाफ 10 वर्ष तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रस्ताव निश्चित रूप से कठोर कदम है। इससे परीक्षा माफिया को स्पष्ट संदेश मिलता है कि सरकार अब इस अपराध को हल्के में नहीं लेगी। लेकिन कानून तभी प्रभावी होगा जब उसके साथ पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, आधुनिक तकनीकी सुरक्षा, जवाबदेही और त्वरित न्याय भी सुनिश्चित किया जाए। देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य केवल कठोर कानून से नहीं, बल्कि उसके निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन से सुरक्षित होगा।

राजीव शर्मा - (संपादक)

अंतरराष्ट्रीय खेल सुविधाओं से लैस होकर बरेली का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा खेल क्रान्ति का नया केन्द्र

उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने और प्रादेशिक खेल प्रतिभाओं को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के ऐतिहासिक संकल्प के तहत जिला स्तर पर खेल अवसरचत्तानामक ढाँचे का अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच और 'खेलोवा यूपी, बड़ेगा यूपी' के मूल मंत्र का धरातल पर उतारते हुए बरेली के ऐतिहासिक स्पोर्ट्स स्टेडियम को सर्वसुविधावाक्य एवं अत्याधुनिक विश्वस्तरीय खेल परिसर के रूप में विकसित करने की दिशा में अत्यंत ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कभी संसदधनों की सीमितता और पुरानी सुविधाओं से जूझता यह पौराणिक स्पोर्ट्समैन अब राज्य सरकार, जिला प्रशासन और खेल विभाग के समन्वित प्रयासों से आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर नई ऊर्जा, नई उम्मीदों और नई दिशा का एक सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है। विकास की इस व्यापक योजना का मुख्य ध्येय केवल कंक्रीट के ढाँचे खड़े करना नहीं, बल्कि एक ऐसा समग्र, सुदृढ़ और भविष्योन्मुखी खेल इकोसिस्टम तैयार करना है, जहाँ बरेली के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के होनहार युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक एवं पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। इस युग्रांतरकारी पहल से बरेली और संपूर्ण रहलखंड मंडल के प्रतिभावान एथलीटों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। बरेली का यह स्पोर्ट्स स्टेडियम दशकों से स्थानीय खिलाड़ियों की मुख्य प्रशिक्षण स्थली रहा है, जहाँ से निकले अनेक एथलीटों ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अद्भुत खेल क्षमता का लोहा मनाया है। हालाँकि, पूर्ववर्ती समय में आधुनिक सुविधाओं का यथेष्ट विस्तार न हो पाने के कारण यहां की अप्रतिम प्रतिभाओं को बेहतर कोचिंग,

आधुनिक उपकरणों और सिंथेटिक कोर्ट्स की तलाश में अन्य बड़े महानगरों की ओर रुख करना पड़ता था। अब इस परिदृश्य को पूरी तरह बदलने और बरेली को एक प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करने के लिए व्यापक पुनर्विकास योजना पर तीव्र गति से कार्य जारी है। इस महापरिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी कड़ी के रूप में हॉकी खेल का पुरोहता शामिल है। एक समय था जब बरेली को हॉकी खिलाड़ियों की समृद्ध नर्सरी के रूप में जाना जाता था, परंतु आधुनिक सिंथेटिक एस्ट्रेटर्फ के अभाव में यह खेल धीरे-धीरे अपनी परंपरिक चमक खोने लगता था और स्थानीय खिलाड़ियों को दैनिक अभ्यास के लिए अन्य जनपदों अथवा राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल सिंथेटिक हॉकी टर्फ के निर्माण से इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है। इस आधुनिक सिंथेटिक टर्फ के पूर्ण होने से बरेली के हॉकी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियमित अभ्यास का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे न केवल उनकी तकनीकी दक्षता में अभूतपूर्व सुधार आएगा बल्कि भारतीय हॉकी टीम, विभिन्न राष्ट्रीय टीमों तथा प्रतिष्ठित पेशेवर लोगों में बरेली के खिलाड़ियों के चयन की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ जाएंगी। हॉकी के साथ-साथ स्टेडियम परिसर में स्थित स्विमिंग पूल का भी व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्षों पुराने इस स्विमिंग पूल को अत्याधुनिक तकनीक, उच्च जल शोधन प्रणाली और सुदृढ़ सुरक्षा मानकों से लैस किया जा रहा है। नया एवं अत्याधुनिक स्विमिंग पूल तैयार होने से तैराकों को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे भविष्य में बरेली में प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं के भव्य आयोजन का मार्ग भी पूरी तरह से प्रशस्त होगा। इसके साथ ही इन दो खेलों को

विकास की इस व्यापक योजना का मुख्य ध्येय केवल कंक्रीट के ढांचे खड़े करना नहीं, बल्कि एक ऐसा समग्र, सुदृढ़ और भविष्योन्मुखी खेल इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां बरेली के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के होनहार युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक एवं पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। इस युगांतरकारी पहल से बरेली और संपूर्ण रुहेलखंड मंडल के प्रतिभावान् एथलीटों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उर प्रदेश का मान बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। बरेली का यह स्पोर्ट्स स्टेडियम दशकों से स्थानीय खिलाड़ियों की मुख्य प्रशिक्षण स्थली रहा है, जहां से निकले अनेक एथलीटों ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अद्भुत खेल क्षमता का लोहा मनवाया है। हालांकि, पूर्ववर्ती समय में आधुनिक सुविधाओं का यथेष्ट विस्तार न हो पाने के कारण यहां की अप्रतिम प्रतिभाओं को बेहतर कोचिंग, आधुनिक उपकरणों और सिंथेटिक कोर्ट्स की तलाश में अन्य बड़े महानगरों की ओर रुख करना पड़ता था।

विशेष प्रोत्साहन देने के क्रम में स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल को पूरी तरह से नया रूप प्रदान किया जा रहा है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिंथेटिक कोर्ट्स, आधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता वाली प्रकाश व्यवस्था, दर्शकों एवं खिलाड़ियों के लिए सर्वसुविधाधारी सीटिंग अरेंजमेंट और उन्नत अथवा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे बैडमिंटन खिलाड़ियों को अपने ही जिले में उत्कृष्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध होगा। फुटबॉल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए भी स्टेडियम के मैदान में व्यापक तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मैदान को पूर्णतः समतल बनाने, उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक घास लगाने और कुशल जल कांसे्रट्रिगणली विकसित करने पर विशेष ध्यान देते प्रकिया गया है। ताकि मानसून के दौरान जलभराव न हो सके और खिलाड़ी वर्षभर निर्बाध रूप से अभ्यास कर सकें। इसके अतिरिक्त, एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए एक एथलेटिक्स सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के निर्माण

की दूरदर्शी योजना बनाई गई है, जो धावकों को चोट-मुक्त अस्थायी वातावरण और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। स्टेडियम परिसर में ही अत्याधुनिक फिटनेस सेंटर, वैज्ञानिक जिम, आधुनिक ड्रेसिंग रूम, प्लेयर्स लाउज, मेडिकल रूम, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, फल-लाइट्स और दर्शक दीर्घा का व्यापक जौर्णोंद्वार किया जा रहा है। ताकि एथलीटों को एक ही छत के नीचे समस्त आवश्यक विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जिले की खेल प्रविष्टियों के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला होती है। जब युवाओं को उनके अपने जनपद में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण कोच और उच्च स्तरीय उपकरण प्राप्त होते हैं, तो वे अपनी क्षमता का शत-प्रशिक्षित प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करते हैं। बरेली स्पोर्ट्स स्टेडियम का यह कायाकल्प केवल खेल जगत तक सीमित न रहकर जिले के सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगा।। बड़े स्टेडियम

के निर्माण से यहां राष्ट्रीय स्तर के खेल शिक्षित, खेल अकादमियां और भव्य खेल आयोजनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापार, पर्यटन, आतिथ्य उद्योग, परिवहन और खानपान व्यवसाय को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर नए अवसर सृजित होंगे। स्थानीय खिलाड़ियों, खेल संघों और खेल प्रेमियों ने प्रशंसा करती और जिला प्रशासन द्वारा संचालित इन विकास कार्यों का अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। लंबे समय से महसूस की जा रही आधुनिक सुविधाओं की मांग पूरी होने से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर मिलेगा और उन्हें प्रशिक्षण हेतु दूरदराज के क्षेत्रों में जाने के आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। यह विकास कार्य प्रदेश सरकार की 'एक जिला-एक खेल' (ओडीओएस) योजना और 'मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय' जैसे युगांतरकारी कदमों की कड़ी में बरेली को खेल क्रांति के शीर्ष पर स्थापित करने का प्रयास है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा पदवी विजेताओं की राई जा रही करोड़ों रुपये की नगद पुरस्कार दी जा रही है। 'कुशल खिलाड़ी योजना' के अंतर्गत सीधे तौर पर सरकारी सेवाओं में राजपत्रित पदों पर नियुक्तियों की ऐतिहासिक नीति ने खिलाड़ियों का मनोबल अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। बरेली स्पोर्ट्स स्टेडियम का यह भव्य पुनर्विकास उन्नत प्रदेश को देश की 'स्पोर्ट्स कैपिटल' के रूप में स्थापित करने के प्रदेश सरकार के व्यापक और दृढ़ संकल्प का एक सशक्त प्रतीक है, जो आने वाले वर्षों में बरेली से अनगिनत अंतरराष्ट्रीय चौपियन तैयार कर विश्व पटल पर भारत के तिरंगे की शान बढ़ाएगा।

**सूचनाधिकारी जनपद-बरेली/
डॉ० सीमा गुप्ता (से०नि० सहा०निदे०)**

सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग कुशल चालकों को ही देगा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ लंबे समय से एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग सड़क हादसों में घायल होते हैं और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में अव्यवस्थित चालक प्रशिक्षण, यातायात नियमों की अनदेखी तथा अनुभवहीन चालकों द्वारा वाहन संचालन शामिल हैं। इन चुनौतियों को पारित करने में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (मोर्धे) ने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा चालक प्रशिक्षण व्यवस्था को वैज्ञानिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस दिशा में केंद्रीय मोटरवाहन निगमावली, 1989 में संशोधन करते हुए प्रत्यायन (प्रमाणन) प्राप्त चालक प्रशिक्षण केन्द्र (Accredited Driver Training Centre - ADTC) की स्थापना एवं संचालन से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन प्रावधानों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल प्रशिक्षित, दक्ष एवं सक्षम चालक ही स्थायी सड़क सुरक्षा लाभ प्राप्त करेंगे। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि देश में सार्वजनिक और जिम्मेदार ड्राइविंग

संस्कृति का भी विकास होगा। नई व्यवस्था के अंगरंग चालक प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक तकनीक, मानकीकृत पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों तथा निर्धारित मात्राओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को केवल वाहन चालना ही नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि सड़क सुरक्षा के नियम, यातायात संकेत, आपातकालीन परिस्थितियों में निर्यत लेने की क्षमता, वाहन रख-रखाव, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में सुशिक्षित वाहन संचालन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार चालकों का निर्माण करना है जो सड़क पर स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों को सुरक्षा का भी ध्यान रखें। प्रत्यानव चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं उनके रख-रखाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक संस्थानों के आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही

स्वीकार किए जाएंगे। अब तक इस प्रक्रिया के लिए विभाग में ऑफलाइन व्यवस्था लागू थी, जिसके कारण दस्तावेजों के सत्यापन, निगरानी एवं अनुमोदन में अधिक समय लगता था। नई ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद आवेदन, आवश्यक अभिलेखों का अपलोड, निरीक्षण, अनुमोदन तथा निगरानी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी तथा अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप भी कम होगा। परिवहन विभाग द्वारा पोर्टल को शीघ्र ही लाइव किए जाने की तैयारी अंतिम चरण में रहा तथा इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक आईडीडीआर (इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड रिचर्स) तथा आईडीडीआई (इंड्रियल ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट) को छोड़कर प्रदेश के 58 जनपदों में प्रत्यायन चलक प्रशिक्षण केन्द्रों से संबंधित कार्यवाही ऑफलाइन माध्यम से की जा रही थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सभी जनपदों में आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इस डिजिटल प्रणाली से प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थाना, मान्यता, निरीक्षण तथा

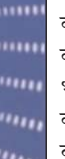
संचालन की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। नई नीति के अनुसार प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कम से कम प्रत्येक प्रत्यायन चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को तक गृहणव्यवस्थापूर्ण चालक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के इच्छुक अस्थायी आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 21 जनपदों में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। आगामी समय में निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भी इन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, जिससे प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षित चालक तैयार किए जा सकें। प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार दोनों ही सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि सड़क सुरक्षा पर वही व्यक्ति वाहन चलाए जिससे निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। प्रशिक्षित चालक न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का बेहतर पालन करते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी काफी कम हो जाती है। प्रदेश के मध्यमार्ग

श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए समय-समय पर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी लाना है। इसी उद्देश्य को पूर्ण के लिए चालक प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण अपर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त चालक होने हैं। यदि चालक को वाहन संचालन की तकनीकी जानकारी, सड़क सुरक्षा नियमों का पर्याप्त ज्ञान तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, तो दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। प्रत्यानुरूप चालक प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली, सिमुलेटर, व्यवहारिक अभ्यास तथा नियमित मूल्यांकन के माध्यम से अभ्यर्थियों की दक्षता विकसित की जाएगी। इससे केवल लाइसेंसधारी चालकों ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार एवं सुरक्षित चालक तैयार होंगे।

-आशीष सिंह, अनुवादक

एआई के दौर में केबीसी का नया अंदाज

तीन जुलाई 2000 को स्टार प्लस टेलिविजन चैनल पर 'कौन बनेगा करोड़पति' कार्यक्रम का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ था। तब से आज तक पिछले 17 सीज़नों में इस कार्यक्रम के 1454 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। किसी एक एपिसोड का आकर्षण उसके पहले वाले से कमतर नहीं रहा। करीब 26 सालों से जारी 'कौन बनेगा करोड़पति' भारतीय टेलिविजन इतिहास का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय विजय शो बना हुआ है। आगामी 9 अगस्त 2026 से इसका 18वां सीज़न शुरू हो रहा है, जो अब तक के सीज़नों से थोड़ा हटकर होगा। इस सीज़न की थीम है— 'सोचना पड़ेगा।' दरअसल एआई के इस दौर में जब किसी भी सवाल का जवाब पलक झपकते मिल सकता हो, उस समय केबीसी को अपनी रणनीति में इस तरह का बदलाव लाना ही होगा कि किसी भी सवाल का जवाब पलक झपकते ही, किसी कृत्रिम



वजह क्या है? दरअसल, केबीसी हमारे ज्ञान और सपनों का संगम है। जहाँ बाकी टीवी कार्यक्रमों को लेकर दिल में यह भावना रहती है कि इन गढ़ी गयी कहानियों से हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वहीं केबीसी के बारे में दिमाग में आता है कि हम एक ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं, जो मनोरंजन करने के साथ ही हमारा ज्ञान भी बढ़ा रहा है। ज्ञान को लेकर समाज के अल्पचेतन में सम्मान को भावना है, इसलिए 'कौन बनेगा करोड़पति' पहली ही सीढ़ी में अपने दर्शकों का सम्मान अर्जित कर लेता है। क्योंकि हर कोई ज्ञान हासिल करना चाहता है। केबीसी की सफलता के पीछे यह नैतिक धारणा सबसे बड़ी चीज है। केबीसी के संबंध में दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम का हमारी महत्वाकांक्षाओं के साथ मजबूत जुड़ाव है।

छोटे शहरों व गांवों के आम लोगों तक को यह कार्यक्रम अपने साथ जोड़ता है। हर किसी में उम्मीद बनाये रखता है कि कोई भी अपनी मेहनत और ज्ञान के बूते कोसों दूर तक बन सकता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के होस्ट अमिताभ बच्चन हैं, जिनकी 50 साल की फिल्मी प्रोफाइल विश्वसनीय है।

अकारण नहीं है कि अब तक के प्रसारित 17 सीज़नों में सिर्फ एक सीज़न (साल 2007) शाहरुख खान ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया था बाकी सभी सीज़नों के होस्ट/होस्टेस अमिताभ बच्चन ही रहे हैं। ऐसे में केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ना कार्यक्रम के लिए है। उनका इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का जो आवसीय हंसा है, वह सम्मानजनक और सहज हास्य लिए होता है, जो कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। वहीं इस कार्यक्रम में अब तक लगभग हर गांव, शाह के चुका प्रतिनिधित्व भी है। किसान, शिक्षक, डॉक्टर, गृहिणी, छात्र, पुलिसकर्मी यानी

समाज के हर वर्ग के लोग अब तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। केबीसी में हर बार इस तरह के बदलाव किये जाते हैं, जिससे पिछले सीजन के मुकाबले मौजूदा सीजन अलग, जरा बेहतर और आसान भी लगता है। केबीसी ने पिछले 17 सीजनों में कई तरह के नियम बदले हैं, कई तरह की सहीूलनयें बढ़ायी हैं। लाइफलाइन, पुरस्कार राशि, खेल के नियम, सुपर सवाल जैसे बदलाव दर्शकों को आकर्षित करते रहे हैं। इस बार का बदलाव यानी 18वें सीजन में सवालों की प्रकृति को इस तरह का किया जा रहा कि अब झटके में और पकस जवान न हों बल्कि जवाब सोचना पड़े, वह भी नये समय की चुनौतियों को देखते हुए काफी लोकप्रिय साबित हो सकता है। क्योंकि आज चैटजीपीटी, गूगल और एआई टूल्स की वजह से जानकारीयें सैकेंडों में मिल रही हैं। तथ्य जानकारि सवाल ज्यादा चुनौती नहीं पैदा करेंगे।

